भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2088

दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

सतत विकास लक्ष्य

2088. **श्री सेल्वाराज वी.:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को 2030 तक पूरा करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न लक्ष्यों के टारगेट को पूरा करने में अब तक हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), पीएम आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा), मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन (जेजेएम), स्वच्छ भारत मिशन, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल (लाइफ), आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम, स्टार्ट-अप इंडिया, शहरी परिवर्तन के कायाकल्प के लिए अटल मिशन (अमृत) शामिल हैं। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उप-राष्ट्रीय स्तर की निगरानी रूपरेखा विकसित करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें सतत विकास लक्ष्यों पर नज़र रखने में मदद मिलती है। यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, एसडीजी स्थानीयकरण को बढ़ावा देती है, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करती है।

(ख) वर्ष 2018 से अब तक एसडीजी इंडिया सूचकांक के चार संस्करण जारी किए जा चुके हैं। एसडीजी इंडिया सूचकांक का नवीनतम संस्करण 2023 में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट एसडीजी की दिशा में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालती है, वर्ष जो 2020-21 के 66 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 71 तक समग्र स्कोर में उल्लेखनीय सुधार दिखाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई प्रगति का विवरण सार्वजनिक रुप से उपलब्ध है और इसे https://www.niti.gov.in/reports-sdg पर देखा जा सकता है।

*****